प्रदेश का किसान स्मार्ट फार्मिंग कर कृषि निर्यात में अग्रणी बनेगा- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026 की तैयारियों की समीक्षा की

जयपुर, 29 दिसम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ करने तथा कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के किसान आधुनिक तकनीकों के माध्यम से स्मार्ट फार्मिंग कर कृषि निर्यात के क्षेत्र में अग्रणी बनें। इसी सोच के साथ, आगामी वर्ष में प्रदेश के किसानों के लिए ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026 (ग्राम) का आयोजन किया जा रहा है।

शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आगामी वर्ष में आयोजित होने वाले ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट-2026 की तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में नवाचार और आधुनिक तकनीक के माध्यम से नए आयाम स्थापित करने के साथ ही निवेश को प्रोत्साहित करना है।

उन्होंने कहा कि इस आयोजन में कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों का भी सम्मान किया जाए। साथ ही, आयोजन की प्रत्येक गतिविधि में किसान की आवश्यकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में देश-विदेश में उन्नत कृषि, जल प्रबंधन, फसल विविधीकरण जैसे नवाचारों को उपयोग में लाने वाले कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिकों तथा तकनीकी जानकारों को आमंत्रित किया जाए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

उन्होंने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से राजस्थान की कृषि क्षमताओं को अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलेगा। शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आयोजन को लेकर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, जिससे ग्रामीण स्तर पर किसानों को कार्यक्रम एवं योजनाओं की जानकारी मिल सके।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस आयोजन में देश-विदेश में उन्नत कृषि, जल प्रबंधन, फसल विविधीकरण जैसे नवाचारों को उपयोग में लाने वाले कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिकों तथा तकनीकी जानकारों को आमंत्रित किया गया है।**

बैठक में बताया गया कि इस एग्रीटेक मीट में कृषि एवं पशुपालन से संबंधित प्रदर्शनी, बीटूजी और बीटूबी मीटिंग, किसान-वैज्ञानिक संवाद, क्रेता-विक्रेता मीटिंग तथा विभिन्न तकनीकी सत्र और कार्यशाला आयोजित किए जाएंगे। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

उद्धव ठाकरे ने अपने प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह दिये

मुंबई, 29 दिसंबर। महाराष्ट्र में शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के साथ गठबंधन की घोषणा के तुरंत बाद पार्टी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह के लिए अधिकृत करने वाले एबी फॉर्म का वितरण शुरू कर दिया है।

रविवार रात से ही जिन उम्मीदवारों के नाम तय हो गए थे, उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया गया और उन्हें बिना किसी देरी के मातोश्री पहुंचने के लिए कहा गया। ठाकरे ने हर उम्मीदवार से अलग-अलग मुलाकात की। उनसे संक्षिप्त चर्चा की और व्यक्तिगत रूप से आधिकारिक एबी फॉर्म सौंपे, जो पार्टी की चुनाव मोड में तेजी से आगे बढ़ ने की तैयारी का संकेत है।

- **उन्होंने बीएमसी चुनाव के लिए अपने हरेक उम्मीदवार से अलग-अलग मुलाकात की।**

पार्टी सूत्रों का कहना है कि गठबंधन सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत आगे बढ़ ने पर जल्द ही अतिरिक्त उम्मीदवारों की सूची घोषित होने की उम्मीद है।

मार्च में भारी फेरबदल हो सकता है, संघ के संगठनात्मक ढांचे में

मार्च में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में ये निर्णय लिए जाएंगे, जो जनवरी 2027 से लागू होंगे

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) मार्च में संगठन में बड़े संगठनात्मक परिवर्तन करने की योजना बना रहा है। संगठनात्मक बदलाव सम्बंधी निर्णय संगठन के बारे में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था, "अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा" द्वारा लिये जायेंगे। यह परिवर्तन जनवरी 2027 से प्रभावी हो सकते हैं।

आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल ने जबलपुर में 30 अक्टूबर और 1 नवम्बर को हुई अपनी बैठक में संगठन में समग्र बदलावों पर चर्चा की थी, लेकिन कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया जा सका था। अब जो मुद्दे प्रतिनिधि सभा में चर्चा के लिए सूचीबद्ध किये गये हैं, उनमें संगठन का विकेन्द्रीयकरण भी शामिल है।

आरएसएस में होने वाले बदलावों के परिणामस्वरूप, भाजपा और आरएसएस के बीच समन्वय में भी बदलाव आएगा, क्योंकि आजकल आरएसएस प्रचारक राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भाजपा संगठन का संचालन करते हैं।

सूत्रों के अनुसार, विचार यह है कि राज्य स्तर पर संगठन चलाने की नीति को समाप्त किया जाए। जबलपुर बैठक में चर्चा की गई योजना के अनुसार, 46 राज्यों को 75 या अधिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, ताकि नेतृत्व और जमीनी स्तर की इकाइयों के बीच की दूरी को कम किया जा सके और तेजी से निर्णय लिये जा सकें। इस प्रक्रिया में आरएसएस द्वारा किये जाने वाले सामाजिक कार्यों पर जोर दिया जाएगा, तथा इसमें अधिक से अधिक युवाओं की भूमिका होगी। यह निर्णय चरणबद्ध रूप से किए जाने वाले परिवर्तनों का हिस्सा है, जिसमें 11 क्षेत्रीय इकाइयों को घटाकर 9 किया जाएगा, और कई राज्यों, जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को एक ही क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। राजस्थान इकाई को उत्तरी राज्यों के साथ जोड़ने की योजना है। योजना के अनुसार, प्रान्त-प्राचरकों की जगह, राज्य प्रचारक नियुक्त किये जायेंगे। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में सात प्रान्त प्रचारकों की जगह सिर्फ एक राज्य प्रचारक होगा। इस योजना में 75 या और अधिक संभागों का सृजन किया जाएगा, तथा प्रत्येक संभाग में एक संभागीय प्रचारक होगा। लेकिन जिला प्रचारक और विभागीय प्रचारक की वर्तमान व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

- **30 अक्टूबर को जबलपुर में हुई बैठक में अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल ने संघ के ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन पर चर्चा की थी, पर, कोई निर्णय नहीं हुआ। अब इस पर प्रतिनिधि सभा में विचार होगा।**
- **इनमें सबसे प्रमुख मुद्दा है, संगठन के विकेन्द्रीकरण का, सूत्रों ने कहा कि राज्य स्तर पर संगठन के संचालन की व्यवस्था कम करके और 46 राज्यों को 75 या उससे अधिक भागों में बांटने पर चर्चा हो रही है ताकि नेतृत्व व निचले स्तर की इकाइयों के बीच दूरी कम से कम हो।**
- **इस बदलाव से संघ व भाजपा के रिश्तों में भी भारी बदलाव आ सकता है।**

सूत्रों ने बताया कि संगठनात्मक परिवर्तनों पर संवाद कई वर्षों से चल रहा था, लेकिन आरएसएस के शताब्दी वर्ष के दौरान इसे लागू न करने का निर्णय लिया गया था।

बांग्लादेश में अंतरिम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इसके अलावा, भारत के सीमा सुरक्षा बल ने ढाका पुलिस के आरोपों को अविश्वसनीय बताया है। मेघालय सेक्टर की सीमा ढाका से कम से कम 300 किलोमीटर दूर है और इतनी हाई-प्रोफाइल वारदात के बाद कोई फरार व्यक्ति इतनी लंबी दूरी बिना पकड़े गए तय नहीं कर सकता।

इसके अलावा भारत के सुरक्षा तंत्र ने यह भी कहा कि बांग्लादेश में व्यापक सीसीटीवी कवरेज है और इस तरह के मूवमैंट को ढाका में ही या सीमा पर किसी न किसी सीसीटीवी नेटवर्क ने ज़रूर पकड़ा होगा। सवाल यह है कि वे सीसीटीवी रिकॉर्ड का विश्लेषण क्यों नहीं कर पा रहे हैं और यह पता क्यों नहीं लगा पा रहे हैं कि आरोपी कैसे फरार हुए।

हक़ीक़त यह है कि बांग्लादेश में क़ानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और वहां की एजेंसियां भी ठीक से काम नहीं कर रही हैं। केन्द्रीय सत्ता के अभाव में निचले स्तर की सरकारी इकाइयां भी निष्क्रिय हो गई हैं।

कुछ भारतीय एजेंसियों का मानना है कि जब तक बांग्लादेश में एक ठीक से चुनी हुई सरकार सत्ता में नहीं आती, तब तक ऐसे अपराध आम हो सकते हैं।

लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि चुनाव वास्तव में स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं या नहीं। फिलहाल राज्य के पास ऐसे चुनाव सुनिश्चित करने की मशीनरी भी नहीं हैं।

यहां तक कि अगर चुनाव होते भी हैं, तो वे बनावटी हो सकते हैं और एकतरफ़ा साबित हो सकते हैं। इस तरह से चुनी हुई सरकार के पास स्वच्छ और प्रभावी शासन चलाने के लिए नैतिक विश्वसनीयता बहुत कम होगी।

इस बीच, बांग्लादेश में दिनदहाड़े हुई दो हिंदू पुरुषों की हत्या की कई देशों ने कड़ी निंदा की है। अमेरिका के एक सांसद ने इन हत्याओं को भयावह बताया है। वे बांग्लादेश में उचित सरकार की बहाली की मांग कर रहे हैं।

मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने में विफल रही है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग गंभीर रूप से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और अल्पसंख्यकों पर हमलों की घटनाएं सामने आई हैं।

हर तरफ से आलोचक यही कह रहे हैं कि बांग्लादेश में धार्मिक कट्टरता बहुत बढ़ गई है और देश को फिर से सामान्य स्थिति में लौटना चाहिए। अंतरिम सरकार को तुरंत यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यकों पर हमले तुरंत बंद हों। साथ ही, अल्पसंख्यक समुदायों के बीच सरकार के प्रति भरोसा और विश्वास बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।

ओमान रवाना हुआ इंजन रहित जहाज कौण्डिन्य

नई दिल्ली, 29 दिसंबर। नौसेना का इंजन रहित पारंपरिक समुद्री जहाज आईएनएसवी कौण्डिन्य सोमवार को अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर पोरबंदर से ओमान के मस्कट के लिए रवाना हुआ। ओमान रवाना हुआ जहाज आईएनएसवी कौंडिन्य पारंपरिक सिलाई विधि का इस्तेमाल करके बनाया गया है। यह पांचवीं शताब्दी के एक जहाज की तर्ज पर बनाया गया है और प्राचीन अजंता गुफाओं के एक चित्र से प्रेरणा लेकर इसे बनाने का विचार आया था।

इस जहाज का नाम पौराणिक नाविक कौंडिन्य के नाम पर रखा गया है। कौंडिन्य के बारे में माना जाता है कि उन्होंने प्राचीन काल में भारत से दक्षिण पूर्व एशिया तक की यात्रा की थी। यह जहाज समुद्र तट वाले देश के रूप में भारत की ऐतिहासिक भूमिका का प्रतीक है। कौण्डिन्य अरब सागर पार करते हुए लगभग 1,400 किलोमीटर की दूरी तय कर मस्कट पहुंचेगा।

- **प्राचीन अजंता गुफाओं के चित्रों में बने एक जहाज से प्रेरणा लेकर बना यह जहाज प्राचीन मार्ग से ही ओमान जाएगा। केन्द्रीय संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में नौसेना ने इस जहाज को कमीशन किया।**

महाराष्ट्र का एक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ सहित, 29 शहरी निकायों के चुनाव 15 जनवरी को होंगे और परिणाम अगले दिन घोषित किए जाएंगे।

2023 में हुए एन.सी.पी. के विभाजन से दोनों गुट कमज़ोर हो गए हैं तथा गुटबाजी से, खासतौर से पश्चिमी महाराष्ट्र में, विरोधियों को फायदा हुआ है। एन.सी.पी. की गुटबाजी के कारण भाजपा को हाल के वर्षों में चुनावों में सफलता मिली है। ऐसा प्रतीत होता है कि अजीत पवार इस स्थिति को बदलना चाहते हैं। कुछ समय पहले, उन्होंने अपनी पत्नी को 2024 के लोकसभा चुनावों में अपने चचेरे भाई और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारने के अपने निर्णय पर सार्वजनिक रूप से अफसोस जताया था। उन्हें ऐसी आशा है कि शरद पवार गुट के साथ एकता की उनकी कोशिश से "महायुति" गठबंधन में सत्ता की सौदेबाजी करने के मामले में उनकी स्थिति मजबूत एवं बेहतर होगी। उनके इस कदम से यह संदेश भी जाएगा कि पवार परिवार महाराष्ट्र राजनीति के केन्द्र में बना हुआ है। इस समय, यह सुलह अस्थायी प्रतीत होती है, लेकिन इससे कुछ बड़े सवाल उठ रहे है, क्या इस एकीकरण को स्थानीय नगर निकाय चुनावों तक सीमित एक अस्थायी कदम माना जा सकता है? या यह राज्यस्तरीय गठबंधनों पर भी असर डालने वाला कदम साबित हो सकता है?

रेत के टीलों में घोंसला बनाने वाले पक्षियों के लिये परियोजना बनेगी

नयी दिल्ली, 29 दिसंबर। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन - एनएमसीजी की कार्यकारी समिति की सोमवार को 68वीं बैठक हुई जिसमें गंगा और उसकी सहायक नदियों में अविरल और निर्मल प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये। बैठक में गंगा बेसिन में लुप्तप्राय पक्षियों के संरक्षण के लिए, भारतीय स्किमर प्रजाति के पक्षी सहित रेत के टीलों पर घोंसला बनाने वाले पक्षियों के प्रजनन स्थलों की सुरक्षा हेतु नयी परियोजना को स्वीकृति दी गई।

शनिवार को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गांधी की भूमिका को लेकर गंभीर चर्चा चल रही है, क्योंकि कई नेता और कार्यकर्ता सोनिया गांधी, खड़गे और यहां तक कि राहुल गांधी से भी मिलकर मांग कर रहे हैं कि प्रियंका को संगठन चलाने में केन्द्रीय भूमिका दी जाए। वे एआईसीसी महासचिव हैं, पर उनके पास कोई जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन हाल के दिनों में राहुल गांधी की अनुपस्थिति में संसद में वे सक्रिय रही हैं और इस पर पार्टी का ध्यान गया है। शक्तिशाली के.सी. वेणुगोपाल भी विवाद के केन्द्र में हैं। वे राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं और संगठन पर उनका नियंत्रण है, जिससे कई महासचिव नाराज़ हैं, क्योंकि उनके पास काम ही नहीं बचा है और ज्यादातर फैसले के.सी. वेणुगोपाल ही लेते हैं।

सूत्र बताते हैं कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी दोनों का मानना है कि वेणुगोपाल को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें जरूरत से ज्यादा ताकत दे दी गई है। उन्होंने ही राहुल गांधी को यह समझाने में अहम भूमिका निभाई है कि अगर प्रियंका को कोई महत्वपूर्ण पद दिया गया तो वे एक वैकल्पिक शक्ति केन्द्र बन जाएंगी और राहुल को पीछे छोड़ देंगी।

दिलचस्प बात यह है कि दिग्विजय सिंह ने पहले ट्वीट किया और फिर सीडब्ल्यूसी में अपनी बात रखी, लेकिन किसी ने भी उनकी खुलकर आलोचना नहीं की। केवल माणिकम टैगोर ने उनके खिलाफ बोला, लेकिन उन्हें वेणुगोपाल के करीबी के रूप में जाना जाता है और कई लोगों का मानना है कि दिग्विजय सिंह की अधिकांश आलोचना का निशाना वेणुगोपाल थे, न कि राहुल गांधी।

पार्टी में मंथन शुरू हो गया है और लगातार हो रही बैठकों से लगता है कि नेतृत्व हालात पर पकड़ बनाने और लंबित मुद्दों को सुलझाने की कोशिश कर रहा है।

राहुल गांधी आज रात एक बार फिर छोटी छुट्टी पर यूरोप रवाना हो रहे हैं और नए साल में ही लौटेंगे

इसलिए किसी भी बदलाव के लिए मध्य जनवरी तक इंतज़ार करना होगा, जब 14 जनवरी के बाद शुभ काल शुरू होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार और हत्या के आरोपी सेंगर की जमानत रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील पर पहली ही सुनवाई में यह फैसला सुनाया

नयी दिल्ली, 29 दिसंबर। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी ठहराए गए कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी ज़मानत पर रोक लगा दी।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जे के महेश्वरी और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज की पीठ ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर अपील पर पहली ही सुनवाई में यह आदेश पारित किया। पीठ ने कहा कि मामले के विशेष तथ्यों को देखते हुए विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाई जाती है। सेंगर को उक्त आदेश के आधार पर हिरासत से रिहा नहीं किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक सेंगर को ट्रायल कोर्ट से सज़ा मिलने के बाद मामला उच्च न्यायालय में गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अगली सुनवाई तक सेंगर की सज़ा निरस्त कर दी थी।

- **सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले के विशेष तथ्यों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाती है।**

पीठ ने कहा कि सामान्यत: जब किसी दोषी या विचाराधीन कैदी को निचली अदालत या उच्च न्यायालय द्वारा ज़मानत दी जाती है, तो बिना उसे सुने उस आदेश पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। लेकिन इस मामले में उत्तरदाता भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत एक अन्य मामले में दोषी ठहराया जा चुका है और उस मामले में भी हिरासत में है।

उच्चतम न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पीड़िता को विशेष अनुमति याचिका दायर करने का वैधानिक अधिकार है और इसके लिए उसे न्यायालय से अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसे नि:शुल्क कानूनी सहायता चाहिए तो सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वह अपने निजी वकील के माध्यम से भी अपील दायर कर सकती है।

सुनवाई के दौरान, बचाव पक्ष की आपत्तियों को स्वीकार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने पीड़िता के वकील को फटकार लगाई, जिन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा ज़मानत दिए जाने में न्यायाधीशों की मिलीभगत का आरोप लगाया था। बचाव पक्ष ने कहा कि इस तरह के बयान राष्ट्रीय टेलीविजन पर दिए जा रहे हैं और ये न्यायालय की अवमानना की सीमा में आते हैं। मुख्य न्यायाधीश ने पीड़िता के वकील को चेतावनी देते हुए कहा कि यह न भूलें कि सेंगर को दोषी ठहराने वाली भी न्यायपालिका ही है। न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश न करें। यह टिप्पणी पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में धारा 304 के तहत सेंगर की सज़ा के संदर्भ में की गई।

उल्लेखनीय है कि सेंगर ने अपनी सज़ा के विरुद्ध अपील लंबित रहने के दौरान सज़ा निलंबन की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था।

ललित मोदी ने वायरल वीडियो डिलीट किया और माफी मांगी

नई दिल्ली, 29 दिसंबर। लंदन में धूमधाम से मनाई गई विजय माल्या की 70वीं बर्थडे पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में पूर्व आईपीएल चेयरमैन ललित मोदी खुद को और माल्या को भारत के दो सबसे बड़े भगोड़े बता रहे हैं। दोनों हंसते हुए यह बात कहते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है।

ललित मोदी ने यह क्लिप इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी, कैप्शन में लिखा था - भारत में इंटरनेट पर फिर से तहलका मचाने का समय आ गया है। हैप्पी बर्थडे मेरे दोस्त विजय माल्या। लव यू। इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर जैसे आग लगा दी और लोग इसपर नाराज हो रहे थे। वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद ललित मोदी ने इसे डिलीट कर दिया। लेकिन विवाद थम नहीं रहा था। लोगों ने लिखा कि ये दोनों भारत से भागकर लंदन में ऐश कर रहे हैं और कानून का मजाक बना रहे हैं। ललित मोदी ने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट कर इस मामले में माफी मांगी है। उन्होंने लिखा, "अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, खासकर भारतीय सरकार को, जिसके लिए मेरे मन में सबसे ऊंचा सम्मान है, तो मैं माफी मांगता हूं। मेरी बात को गलत समझा गया, ऐसा कभी इरादा नहीं था। एक बार फिर दिल से माफी मांगता हूं।"

- **ललित मोदी ने विजय माल्या की बर्थडे पार्टी का वीडियो शेयर कर कहा था, हम दोनों भारत के सबसे बड़े भगोड़े हैं**

इस विवाद पर विदेश मंत्रालय ने भी प्रतिक्रिया दी। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि कानून के जरिए भगोड़े लोगों को वापस लाया जाए और यहां अदालत में ट्रायल का सामना कराए। उन्होंने बताया कि कई देशों से बात चल रही है और प्रक्रिया जारी है।

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बढ़ती चिंता के बीच लिया गया, क्योंकि इसे लेकर आशंका जताई जा रही थी कि इससे पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों में खनन और निर्माण के रास्ते खुल सकते हैं।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस निर्णय का स्वागत किया, लेकिन चेतावनी दी कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।

उन्होंने एक्स पर लिखा, "परिभाषा का मुद्दा फिर से जांचा जाएगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसका विरोध कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट की केन्द्रीय सशक्त समिति इसका विरोध कर रही थी। यह एक स्वागत योग्य संकेत है, लेकिन संघर्ष लंबा है, क्योंकि हमें इसे खत्म करना होगा। यह पर्यावरण के लिए एक अंतरिम जीत है। यह किसी राजनीतिक पार्टी या व्यक्ति की जीत नहीं है। यह भारत के पर्यावरण को बचाने के लिए किये जा रहे संघर्ष की जीत है, ताकि हम सांस ले सकें।"

विशेषज्ञों का कहना है कि इस घटना ने यह दिखा दिया है कि भारत में अरावली श्रृंखला की परिभाषा और संरक्षण के तरीके में एक गहरी समस्या है। वे चेतावनी देते हैं कि इस परिवर्तन से 700 किलोमीटर लंबी अरावली श्रृंखला के विशाल क्षेत्रों को खनन और निर्माण के लिए खोला जा सकता है, जिसके परिणाम धीरे-धीरे, लेकिन अपरिवर्तनीय रूप से, सामने आ सकते हैं।

इकोलॉजी और पर्यावरण विशेषज्ञ सलीम खान ने कहा, "जो हम आज देख रहे हैं, वह मुख्य रूप से एक भूगर्भीय श्रेणीकरण है। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से, इस दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण सीमाएं हैं।"

डॉ. खान ने कहा, अरावली पर्वत केवल कुछ पहाड़ियों का समूह नहीं हैं, जिन्हें ऊंचाई से मापा जा सकता है। ये इकोलॉजी की दृष्टि से महत्वपूर्ण काम करती हैं, जैसे तापमान का नियंत्रण, जलभूमि का पुनर्भरण, मिट्टी का संरक्षण और बीज का प्रसार, जो केवल ऊंचाई के साधारण मानदंड से मेल नहीं खाते।

उन्होंने कहा, "कई पर्वतों के बीच का कॉरिडोर, निचले ढलान और मौसमी जलधाराएं 100 मीटर से अधिक ऊंची नहीं होतीं। केवल ऊंचाई के आधार पर इन क्षेत्रों को बाहर करना पारिस्थितिकी तंत्र की संपूर्णता के लिए महत्वपूर्ण घटकों को नज़रअंदाज करने का जोखिम हो सकता है," उन्होंने यह भी जोड़ा कि इसमें सिर्फ भूविज्ञान ही दांव पर नहीं है, बल्कि इससे भी बहुत कुछ ज्यादा दांव पर है।

प्रोफेसर शिवाजी सरकार ने कहा, छोटे व्यवधान से भी जलग्रहण क्षमता तीव्रता से घट सकती हैं और मरुस्थलीकरण को बढ़ावा दे सकती हैं। पारिस्थितिकी अनुसंधान लगातार यह दिखाता है कि इससे पारिस्थितिकी तंत्र पर भारी असंतुलित प्रभाव पड़ सकता है, जिसे पलटा नहीं जा सकता।

प्रो. सरकार ने कहा, "यह बहुत पुरानी पर्वत श्रंखला है, जिनमें कम गहरे और कमज़ोर हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, इन्हें सहेजने की जरुरत है, "निचले ढलानों और जुड़े हुए भूमि रूपों के विघटन, समय के साथ भूजल रिचार्ज व्यवस्था बाधित हो जाएगी, जिससे मरुस्थलीकरण का खतरा बढ़ सकता है।"

पर्यावरण कार्यकर्ता और पारिस्थितिकी संरक्षण विशेषज्ञ शांतनु द्विवेदी ने कहा, अदालत ने पहले निर्णय में नई परिभाषा को "केवल दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरे अरावली क्षेत्र को प्रदूषण और विकिरण से बचाने की उम्मीद की रेखा" के रूप में बताया था।

उन्होंने अरावली को इकोलॉजी का खजाना बताते हुए कहा, "अगर सुप्रीम कोर्ट ने खनन या किन्हीं अन्य 'विकासात्मक' गतिविधियों की अनुमति दी, तो इसका मतलब होगा कि 90 प्रतिशत अरावली समाप्त हो सकती है। बढ़ते वायु प्रदूषण के संदर्भ में, यह निर्णय, जबकि सुप्रीम कोर्ट दीर्घकालिक उपायों की बात करता है, वास्तव में उन प्राकृतिक सुरक्षा उपायों का शोषण करता है, जिन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए।"

अरावली पर्वत वह स्त्रोत हैं, जिससे चंबल, साबरमती और लूनी जैसी नदियाँ निकलती हैं, और उनके वन, घास के मैदान और नम भूमि लुप्तप्राय पौधों और जानवरों को पनपाती है।

इनमें से कई प्रजातियाँ सबसे ऊंचे शिखरों पर निर्भर नहीं होतीं, बल्कि निचले पहाड़ों और घाटियों पर निर्भर होती हैं, जो अब खतरे में हैं।

भाजपा ने मुंबई नगर निगम के लिये प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की

मुंबई, 29 दिसंबर। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के बीच नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन तक सीटों के बंटवारे पर बातचीत बेनतीजा रहने के बाद, भाजपा ने सोमवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी।

पार्टी ने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इनमें से सभी को एबी फॉर्म जारी कर दिये गये हैं, जो जरूरत पड़ने पर पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी का संकेत है। यह कदम मुंबई में दोनों गठबंधन सहयोगियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर फॉर्मूले की अनिश्चितता के बीच उठाया गया है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, यह फैसला आखिरी समय की उलझन से बचने और यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि नामांकन की समय सीमा से पहले भाजपा उम्मीदवार दौड़ में शामिल रहें।

बंगाल में महाकाल का मंदिर बनवाएंगी ममता बनर्जी

प.बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, मैं पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हूँ

कोलकाता, 29 दिसंबर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे तुष्टिकरण के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए खुद को सच्चे अर्थों में धर्मनिरपेक्ष बताया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सभी धर्मों और समुदायों को समान सम्मान देती है और यही उनकी राजनीति की मूल विचारधारा है।

कोलकाता में 'दुर्गा आंगन' कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, कई लोगों ने कहा है कि मैं तुष्टीकरण कर रही हूं, लेकिन मैं सेक्युलर हूं और सभी धर्मों में विश्वास करती हूं। मुझे बंगाल से प्यार है, मुझे भारत से प्यार है। हम सभी जातियों, सभी धर्मों से प्यार करते हैं। यही हमारी विचारधारा है। हर व्यक्ति को अपना लोकतांत्रिक अधिकार है। धर्म व्यक्तिगत पसंद है, लेकिन त्यौहार सभी के लिए हैं। ममता ने कहा कि मैं सभी धर्मों के कार्यक्रमों में जाती हूं, जब मैं गुरुद्वारे जाती हूं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर मैं ईद के कार्यक्रम में जाती हूं तो कुछ लोगों को परेशानी होने लगती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को दुर्गा आंगन की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज का कार्यक्रम बंगाल और बंगाल के लोगों को समर्पित है। मैं समाज के अलग-अलग वर्गों से यहां आने वाले सभी लोगों का धन्यवाद करती हूं। आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि दुर्गा आंगन के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और हमें उम्मीद है कि काम बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। ममता बनर्जी ने बताया कि दुर्गा आंगन के निर्माण के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और इसका लाभ राज्य के लोगों को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्गा आंगन न केवल सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करेगा, बल्कि बंगाल के सामाजिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

- **उन्होंने कहा, मैं गुरुद्वारे जाती हूँ तो किसी को दिक्कत नहीं होती, पर ईद के कार्यक्रम में जाती हूँ तो कुछ लोगों को परेशानी होती है।**

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय:-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908